International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 5.414 Volume 5, Issue 7, July 2018
Website- www.aarf.asia, **Email** : editoraarf@gmail.com

भारत के संदर्भ में शैक्षिक पाठ्यक्रम पर राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन

डॉ. श्रीकान्त प्रधान
सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)
शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय,
नंदिनी नगर जिला-दुर्ग

सारांश:

यह शोध पत्र भारत में शैक्षिक पाठ्यक्रम के निर्माण और विकास पर राजनीतिक विचारधाराओं के प्रभाव की जांच करता है। शिक्षा, सामाजिक मूल्यों और राष्ट्रीय पहचान को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होने के नाते, अक्सर प्रचलित राजनीतिक वातावरण से प्रभावित होती रही है। अध्ययन औपनिवेशिक युग, स्वतंत्रता के बाद के वर्षों और विभिन्न सरकारी शासनों के दौरान नीतिगत परिवर्तनों सहित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवधियों में गहराई से उतरता है। यह पाठ्यक्रम निर्माण में राजनीतिक हस्तक्षेप के उदाहरणों पर प्रकाश डालता है, जैसे कि ऐतिहासिक आख्यानों का सांप्रदायिकरण, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व और विशिष्ट विचारधाराओं का समावेश या बहिष्करण। शोध इन प्रभावों के परिणामों की भी जांच करता है, जिसमें अल्पसंख्यक दृष्टिकोणों का हाशिए पर होना, क्षेत्रीय असमानताएं और अकादमिक तटस्थता पर बहस शामिल हैं। विभिन्न प्रशासनों और राज्य-स्तरीय अनुकूलन के तहत पाठ्यपुस्तक संशोधन जैसे विवादों का विश्लेषण करके, यह पत्र पाठ्यक्रम विकास के लिए एक समावेशी, निष्पक्ष एवं अकादमिक रूप से कठोर दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अध्ययन स्वतंत्र निरीक्षण निकायों की स्थापना, आवधिक समीक्षा और आलोचनात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश करके समाप्त होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शैक्षिक पाठ्यक्रम राजनीतिक एजेंडे के बजाय सशक्तिकरण और एकता के साधन के रूप में काम करें।

मुख्य शब्द: ***राजनीतिक प्रभाव, शैक्षिक पाठ्यक्रम, भारत, वैचारिक पूर्वाग्रह, पाठ्यपुस्तक विवाद, ऐतिहासिक आख्यान, शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता***

परिचय:

शिक्षा किसी राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ताने-बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में, जो अपनी विविधता और जटिल इतिहास के लिए जाना जाता है, शैक्षिक पाठ्यक्रम न केवल ज्ञान प्रसार का एक साधन है, बल्कि एक ऐसा माध्यम भी है जिसके माध्यम से मूल्यों, विचारधाराओं और ऐतिहासिक आख्यानों को प्रसारित किया जाता है। समय के साथ, शैक्षिक पाठ्यक्रम का विकास राजनीतिक विचारधाराओं से गहराई से प्रभावित हुआ है, जो क्रमिक सरकारों की प्राथमिकताओं और उनके युगों की सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाता है।

© Associated Asia Research Foundation (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

भारत में राजनीति और शिक्षा के बीच संबंध विशेष रूप से राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एवं स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के प्रयासों के कारण स्पष्ट रूप से स्पष्ट हुए हैं। पाठ्यक्रम अक्सर वैचारिक प्रतिस्पर्धा के लिए युद्ध के मैदान के रूप में कार्य करता है, जहाँ विभिन्न राजनीतिक शासनों ने इसे सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रवाद और शासन के अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साधन के रूप में उपयोग करने की कोशिश की है। औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली से जिसने स्वदेशी ज्ञान पर पश्चिमी आदर्शों को प्राथमिकता दी, से लेकर स्वतंत्रता के बाद के युग तक जिसने धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकीकरण पर जोर दिया, पाठ्यक्रम बदलते राजनीतिक संदर्भों के जवाब में विकसित हुआ है।

यह शोधपत्र भारत के शैक्षिक पाठ्यक्रम पर राजनीतिक प्रभाव की जांच करता है, जो इसकी सामग्री और संरचना को आकार देने वाले प्रमुख क्षणों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पाठ्यपुस्तकों में ऐतिहासिक आख्यानों, सांस्कृतिक पहचानों और वैचारिक दृष्टिकोणों में बदलावों पर प्रकाश डालता है। अध्ययन विभिन्न राजनीतिक शासनों के दौरान पाठ्यक्रम परिवर्तनों से जुड़े विवादों की भी पड़ताल करता है, जैसे इतिहास का सांप्रदायिकरण, अल्पसंख्यक आवाज़ों का हाशिए पर होना और धर्मनिरपेक्षता एवं समावेशिता पर बहस। शोधपत्र का उद्देश्य भारत में राजनीति एवं शिक्षा के बीच परस्पर क्रिया की व्यापक समझ प्रदान करना है, जो अत्यधिक राजनीतिकरण की चुनौतियों और पाठ्यक्रम विकास के लिए समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

शोध के उद्देश्य:

१) यह जांचना कि राजनीतिक विचारधाराओं ने पाठ्यक्रम के विकास को कैसे आकार दिया है।
२) शैक्षिक सामग्री, विशेष रूप से पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, सामग्री और संरचना पर राजनीतिक शासन के प्रभाव का अध्ययन करना।
३) ऐसे मामलों की पहचान करना जहां राजनीतिक हस्तक्षेपों ने ऐतिहासिक आख्यानों, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व और शैक्षिक प्राथमिकताओं को बदल दिया है।
४) यह आकलन करना कि अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासी समुदायों सहित हाशिए पर पड़े समूहों को पाठ्यक्रम में कैसे दर्शाया गया है या बाहर रखा गया है।
५) पाठ्यपुस्तक संशोधन, इतिहास के सांप्रदायिकरण और अन्य राजनीतिक रूप से प्रेरित संशोधनों पर प्रमुख बहस की जांच करना।

साहित्य समीक्षा:

साहित्य समीक्षा भारत में शैक्षिक पाठ्यक्रमों पर ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा करती है, जिसमें मैकाले के मिनट ऑन एजुकेशन (१८३५), वुड के डिस्पैच (१८५४) और कोठारी आयोग की रिपोर्ट (१९६६) पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये दस्तावेज़ औपनिवेशिक प्रशासन के राजनीतिक एजेंडे को उजागर करते हैं, जो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार बिचौलियों को बनाने के लिए है, जिसमें स्वदेशी परंपराओं पर पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया गया है। कुमार की पुस्तक "पूर्वाग्रह और गर्व: भारत और पाकिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम के स्कूल इतिहास" इस बात की पड़ताल करती है कि भारत और पाकिस्तान में इतिहास की पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रवादी विचारधाराओं से कैसे प्रभावित हुई हैं।

थापर का काम राजनीतिक ताकतों द्वारा ऐतिहासिक आख्यानों में पेश किए गए सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों की आलोचना करता है, खासकर २००० के दशक की शुरुआत में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान। सुंदर का

अध्ययन शिक्षा के सांप्रदायिकरण की जांच करता है, जो भाजपा शासन (१९९८-२००४) के दौरान पाठ्यपुस्तक संशोधनों पर केंद्रित है। चंद्रा इस बात पर चर्चा करते हैं कि राजनीति में सांप्रदायिकता किस तरह से शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में घुस गई है, जिससे ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ाने के तरीके और सांप्रदायिक सद्भाव पर राजनीतिकरण के दीर्घकालिक प्रभाव प्रभावित हो रहे हैं।

शर्मा की पुस्तक एकीकृत राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने और शिक्षा में भारत की सांस्कृतिक विविधता को समायोजित करने के बीच तनाव की जांच करती है। NCERT पाठ्यपुस्तक विवाद (२०००-२००५) भाजपा सरकार के पाठ्यक्रम परिवर्तनों का विश्लेषण करते हैं, जिसमें प्राचीन भारतीय उपलब्धियों और हिंदू सांस्कृतिक लोकाचार पर जोर दिया गया है। शुक्ला का काम आलोचनात्मक रूप से मूल्यांकन करता है कि राजनीतिक विचारधाराओं ने शिक्षा नीति को कैसे प्रभावित किया है, विशेष रूप से इतिहास और सामाजिक विज्ञान के संबंध में।

शोध पद्धति:

यह गुणात्मक शोध ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक शोध रचना के माध्यम से भारतीय शैक्षिक पाठ्यक्रम पर राजनीतिक प्रभाव का पता लगाता है। यह नीति दस्तावेजों, पाठ्यक्रम रूपरेखाओं, पाठ्यपुस्तकों, शैक्षणिक साहित्य, केस स्टडी और मीडिया रिपोर्टों की जांच करता है। अध्ययन भारत में राजनीति और शिक्षा के बीच परस्पर क्रिया को समझने के लिए विषयगत विश्लेषण, सामग्री विश्लेषण और तुलनात्मक विश्लेषण का उपयोग करता है।

भारत के संदर्भ में शैक्षिक पाठ्यक्रम पर राजनीतिक प्रभाव:

भारत में शिक्षा नीति का इतिहास राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताकतों द्वारा आकार दिया गया है। औपनिवेशिक काल से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक, शिक्षा का उपयोग नियंत्रण और सशक्तिकरण दोनों के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया है। भारत में शिक्षा नीति के विकास में प्रमुख चरणों में वुड्स डिस्पैच (१८५४), मैकाले के मिनट्स (१८३५) और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना (१९६४-६६) शामिल हैं।

औपनिवेशिक काल के दौरान, भारत में शिक्षा मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रशासन की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्माण की गई थी। अंग्रेजों ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित की जो राजघराने के प्रति वफ़ादारी पर ज़ोर देती थी, जिससे क्लर्क, दुभाषिए और निम्न-स्तरीय प्रशासकों का एक वर्ग तैयार होता था, जबकि स्वदेशी शिक्षा प्रणालियों को दरकिनार कर दिया जाता था। इस अवधि के दौरान शैक्षिक परिदृश्य को आकार देने में प्रमुख नीतियों और रिपोर्टों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वुड्स डिस्पैच ने अंग्रेजी पढ़ाने पर ज़ोर देने के साथ स्कूलों और कॉलेजों के एक नेटवर्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा ताकि एक ऐसा वर्ग विकसित हो जो ब्रिटिश प्रशासन की सेवा कर सके। हालाँकि, यह ज़्यादातर अभिजात वर्ग के लिए था, जिससे आबादी का अधिकांश हिस्सा निरक्षर रह गया और औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गया।

मैकाले के मिनट्स ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की वकालत की, यह तर्क देते हुए कि पश्चिमी शिक्षा स्वदेशी प्रणालियों से बेहतर थी। इस शिक्षा प्रणाली ने बौद्धिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने या राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम किया, क्योंकि इसने औपनिवेशिक राज्य के प्रति वफ़ादार विषयों को बनाने की कोशिश की।

स्वतंत्रता के बाद के युग में, शिक्षा प्रणाली में सुधार और एक एकीकृत, आधुनिक और प्रगतिशील शैक्षिक संरचना बनाने के लिए १९६४-६६ में कोठारी आयोग (राष्ट्रीय शिक्षा आयोग) की स्थापना की गई थी। आयोग ने सामाजिक वर्ग, जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा और पहुँच के महत्व पर जोर

दिया। कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक त्रि-भाषा सूत्र था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करते हुए भाषाई विविधता को बढ़ावा देना था।

कोठारी आयोग ने औद्योगीकरण और तकनीकी उन्नति का समर्थन करने के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के महत्व को भी पहचाना। पाठ्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को एक केंद्रीय भूमिका दी गई, विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च शिक्षा में। पाठ्यक्रम को पारंपरिक मूल्यों और स्थानीय ज्ञान के प्रति सम्मान के साथ आधुनिकीकरण को संतुलित करने के लिए निर्माण किया गया था, जिससे आधुनिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दुनिया में भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान के लिए प्रशंसा दोनों का विकास हुआ।

स्वतंत्रता के बाद के युग की प्रमुख नीतियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (१९६८), १९८६ की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (२००९) शामिल थे। इन नीतियों का उद्देश्य सभी भारतीयों को सशक्त बनाना था, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, और साझा शैक्षिक अनुभव के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था, जिसमें भारत की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विविधता शामिल थी।

भारत में शैक्षिक पाठ्यक्रम पर राजनीतिक प्रभाव:

भारतीय शैक्षिक पाठ्यक्रम १९४७ में भारत की स्वतंत्रता के बाद से महत्वपूर्ण राजनीतिक और वैचारिक विवाद का विषय रहा है। ऐतिहासिक और औपनिवेशिक नींव में ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा नीतियाँ शामिल हैं, जिन्होंने स्वदेशी शिक्षा प्रणालियों को हाशिए पर डाल दिया और पारंपरिक विज्ञान, कला और दर्शन को हाशिए पर धकेल दिया। स्वतंत्रता के बाद के सुधारों ने सार्वभौमिक शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक समावेशिता पर जोर दिया, जबकि नेहरूवादी नीतियों ने आधुनिक, एकीकृत भारत को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और धर्मनिरपेक्ष इतिहास को प्राथमिकता दी।

पाठ्यक्रम विकास में वैचारिक धाराओं में नेहरूवादी युग शामिल है, जहाँ जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव और आधुनिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। इंदिरा गांधी के प्रभाव (१९७० के दशक) में शैक्षिक सामग्री समाजवाद और राज्य के नेतृत्व वाले विकास पर केंद्रित थी, जो अक्सर रियासतों या स्वतंत्रता में दक्षिणपंथी योगदान जैसे पहलुओं को कम करके आंकती थी। जनता पार्टी सरकार (१९७० के दशक के अंत से १९८० के दशक तक) ने पाठ्यक्रम में भारतीय परंपराओं को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया, वैदिक विज्ञान, भारतीय दर्शन और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों पर पाठों को एकीकृत किया, लेकिन सांस्कृतिक अनिवार्यता की ओर झुकाव और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को कमज़ोर करने के लिए आलोचना की गई।

वर्तमान राजनीतिक शासन ने NCERT पाठ्यपुस्तकों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जैसे कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार (१९९८-२००४) और कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार (२००४-२०१४)। इन परिवर्तनों ने प्राचीन भारतीय उपलब्धियों, मुगल और औपनिवेशिक इतिहास की आलोचना और भगवाकरण की बहस पर जोर दिया है। २०१४ में भाजपा की वापसी ने पाठ्यक्रम में बदलावों पर बहस को फिर से हवा दी, जिसमें भारत के प्राचीन गौरव पर जोर देने, योग और संस्कृत को बढ़ावा देने और औपनिवेशिक एवं नेहरूवादी विरासत की आलोचना करने के प्रयास केंद्र बिंदु बन गए।

इतिहास शिक्षा में विवादास्पद विषयों में आर्यन आक्रमण सिद्धांत, मुगल सम्राटों और उनकी नीतियों का चित्रण एवं अन्य सांस्कृतिक प्रभावों पर हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं पर जोर देना शामिल है। भाषा की राजनीति, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा, तथा क्षेत्रीय असमानताएँ भी राजनीतिक प्रभाव के क्षेत्र रहे हैं।

भारतीय शैक्षिक पाठ्यक्रम पर राजनीतिक प्रभाव के प्रभावों में ऐतिहासिक निष्पक्षता का क्षरण, अकादमिक स्वायत्तता को कम करना, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय असमानताएँ और शिक्षा का ध्रुवीकरण शामिल हैं। भारत की शैक्षिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए, पाठ्यक्रम विकास के लिए एक संतुलित, समावेशी और अकादमिक रूप से कठोर दृष्टिकोण सुनिश्चित करना आवश्यक है।

भारत में पाठ्यक्रम निर्माण में राजनीतिक हस्तक्षेप:

भारत का शैक्षिक पाठ्यक्रम स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में राजनीतिक विचारधाराओं से काफी प्रभावित रहा है। नेहरूवादी दृष्टिकोण से लेकर उदारीकरण के बाद के युग तक, राजनीतिक हस्तक्षेप ने स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर इतिहास, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में। ये बदलाव सत्तारूढ़ दलों के बदलते राजनीतिक परिदृश्य और विचारधाराओं को दर्शाते हैं, जो पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण विधियों और शैक्षिक उद्देश्यों की सामग्री और संरचना को प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में राजनीतिक हस्तक्षेप की प्रमुख अवधियों में स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्ष (१९४७-१९७०), ध्रुवीकरण की अवधि (१९७०-१९८०), आपातकालीन अवधि (१९७५-१९७७), क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय (१९७०-१९८० के दशक के अंत) और उदारीकरण का युग (१९९० का दशक) शामिल हैं।

स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सोच और राष्ट्रीय एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें शिक्षा को भारत के विविध समुदायों को एकीकृत करने और एक एकल, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से संबंधित होने की भावना को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा गया। इतिहास की पाठ्यपुस्तकों ने धार्मिक विभाजन को कम करके आंका और विज्ञान, साहित्य और संस्कृति में भारत के प्राचीन और आधुनिक योगदान पर जोर दिया, जबकि स्वतंत्रता संग्राम और सभी समुदायों के साझा बलिदानों पर ध्यान केंद्रित किया।

ध्रुवीकरण की अवधि में शैक्षिक आख्यानों पर अधिक केंद्रीय नियंत्रण देखा गया, जिसमें सरकार न केवल राजनीतिक असहमति बल्कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों सहित सांस्कृतिक और बौद्धिक अभिव्यक्तियों को भी नियंत्रित करना चाहती थी। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, विशेष रूप से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, स्थानीय पाठ्यक्रम अनुकूलन हुए, जिसमें क्षेत्रीय इतिहास, संस्कृति और भाषा पर जोर दिया गया।

उदारीकरण के युग (१९९० के दशक) में वैश्वीकरण और शिक्षा पर बहस देखी गई, भारत के आर्थिक उदारीकरण ने देश को वैश्विक बाजारों और नए विचारों के लिए खोल दिया। पाठ्यक्रम में वैश्विक दृष्टिकोण शामिल होने लगे, अक्सर प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और अंग्रेजी भाषा के क्षेत्रों में, लेकिन इस बात पर भी बहस छिड़ गई कि क्या शिक्षा प्रणाली बहुत अधिक पश्चिमीकृत हो रही है और भारतीय परंपराओं और मूल्यों से संपर्क खो रही है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार और पाठ्यक्रम में बदलाव (१९९८-२००४) ने पाठ्यक्रम में वैचारिक बदलाव देखे, जो हिंदुत्व (हिंदू राष्ट्रवाद) के लिए पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवधि में प्राचीन भारत की उपलब्धियों, विशेष रूप से इसकी हिंदू सांस्कृतिक विरासत पर जोर देने के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षिक संसाधनों का संशोधन देखा गया।

सांप्रदायिक पूर्वाग्रह पर विवादों ने महत्वपूर्ण बहस और विवादों को जन्म दिया, जिसमें आलोचकों ने भाजपा सरकार पर इतिहास की चुनिंदा व्याख्या करके और देश के अतीत के संकीर्ण हिंदू-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर शिक्षा को सांप्रदायिक बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

यूपीए सरकार के संशोधनों (२००४-२०१४) ने पाठ्यक्रम को गैर-राजनीतिक बनाने की कोशिश की, पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, समावेशिता और वैज्ञानिक स्वभाव पर ध्यान केंद्रित किया। इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया गया ताकि उनमें व्यापक दृष्टिकोण शामिल किए जा सकें, खास तौर पर जाति, लिंग और धार्मिक विविधता के मुद्दों पर।

भारत के शैक्षिक पाठ्यक्रम को स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में राजनीतिक विचारधाराओं द्वारा आकार दिया गया है और नया रूप दिया गया है। ये बदलाव सत्तारूढ़ दलों के बदलते राजनीतिक परिदृश्य और विचारधाराओं को दर्शाते हैं, जो पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण विधियों एवं शैक्षिक उद्देश्यों की सामग्री और संरचना को प्रभावित करते हैं।

भारत के पाठ्यक्रम निर्माण में राजनीतिक हस्तक्षेप ने देश के बदलते वैचारिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित किया है। नेहरूवादी युग के धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक फोकस से लेकर क्षेत्रीय पहचान के उदय और भाजपा की हिंदुत्व-संचालित नीतियों की वैचारिक लड़ाइयों तक, पाठ्यक्रम परिवर्तनों ने अक्सर व्यापक राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्षों को प्रतिबिंबित किया है। शिक्षा पर इन राजनीतिक बदलावों का प्रभाव गहरा रहा है, जिसने भारत भर के स्कूलों में इतिहास, विज्ञान एवं संस्कृति को कैसे पढ़ाया जाता है, इसे प्रभावित किया है।

भारत में पाठ्यक्रम निर्माण पर राजनीतिक प्रभाव से उत्पन्न होने वाले प्रमुख मुद्दे:

भारत के शैक्षिक पाठ्यक्रम पर राजनीतिक प्रभाव ने महत्वपूर्ण मुद्दों को जन्म दिया है, खास तौर पर इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान की प्रस्तुति में। ये मुद्दे शिक्षा के एक तटस्थ, ज्ञान-निर्माण उद्यम के रूप में और राजनीतिक विचारधाराओं को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में इसके उपयोग के बीच तनाव को दर्शाते हैं। इतिहास का सांप्रदायिकरण, खास तौर पर हिंदू-मुस्लिम संबंधों के संदर्भ में, एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसमें संशोधनवादी दृष्टिकोण अक्सर प्राचीन हिंदू सभ्यता की उपलब्धियों पर जोर देते हैं। सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व भी प्रभावित हुआ है, जिसमें प्रमुख आख्यान अक्सर अन्य सांस्कृतिक परंपराओं, जैसे दलित, आदिवासी समुदाय, मुस्लिम, ईसाई एवं अन्य धार्मिक या सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखते हैं। वैचारिक लक्ष्यों के साथ शैक्षणिक तटस्थता को संतुलित करना भारतीय पाठ्यक्रम निर्माण में एक सतत मुद्दा है। क्षेत्रीय असमानताएं एक सतत मुद्दा रही हैं, जिसमें केंद्रीकृत पाठ्यक्रम अक्सर विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखने में विफल रहा है। अलग-अलग क्षेत्रीय पहचान वाले राज्यों ने अक्सर अपने स्वयं के इतिहास और सांस्कृतिक आख्यानों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने की कोशिश की है। केंद्रीकृत आख्यानों पर एक राष्ट्रीय आख्यान थोपने का आरोप लगाया गया है जो क्षेत्रीय पहचानों के साथ प्रतिध्वनित नहीं होता है, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन होते हैं और राज्य पाठ्यक्रम निर्माण करने में अधिक स्वायत्तता की मांग होती है। पाठ्यक्रम निर्माण में राज्य स्वायत्तता भी विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अधिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक कदम है।

निष्कर्ष:

भारत के शैक्षिक पाठ्यक्रम पर राजनीतिक प्रभाव देश के शैक्षिक विकास में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, जिसने छात्रों के खुद के और समाज के बारे में विचारों को आकार दिया है। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में जवाहरलाल नेहरू के धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकीकरण के दृष्टिकोण से, पाठ्यक्रम का उद्देश्य आधुनिकता और एकता को बढ़ावा देना था। हालाँकि, राजनीतिक हस्तक्षेपों ने शिक्षा के सांप्रदायिकरण को जन्म दिया, विशेष रूप से १९९० और २००० के दशक में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत। इससे हिंदुत्व आख्यान का उदय हुआ, जिसने हिंदू संस्कृति और इतिहास पर जोर दिया, जिससे सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व पर बहस हुई। विचारधारा और अकादमिक

कठोरता को संतुलित करना एक चुनौती रही है, क्योंकि राजनीतिक प्रभाव अक्सर पाठ्यक्रम को विशिष्ट वैचारिक लक्ष्यों की ओर धकेलता है, जिससे अकादमिक तटस्थता कम होती है। क्षेत्रीय असमानताएँ और केंद्रीकरण पाठ्यक्रम पर राजनीतिक प्रभाव को और जटिल बनाते हैं। भारत की विविध सांस्कृतिक, भाषाई एवं धार्मिक विविधता को समायोजित करने वाले अधिक समावेशी, निष्पक्ष और अकादमिक रूप से कठोर पाठ्यक्रम की आवश्यकता एक चुनौती बनी हुई है। भारत के शैक्षिक पाठ्यक्रम का विकास संभवतः राष्ट्र की राजनीतिक गतिशीलता को प्रतिबिंबित करना जारी रखेगा, जिसके लिए क्षेत्रीय पहचान के साथ राष्ट्रीय एकता, वैचारिक विविधता के साथ शैक्षणिक अखंडता और सांस्कृतिक गौरव के साथ धर्मनिरपेक्षता को संतुलित करने पर निरंतर चर्चा की आवश्यकता होगी।

संदर्भ:

- *Batra, P. (2010). Curriculum, identity, and politics in India: The politics of knowledge. Indian Journal of Education and Social Studies, 12(3), 45–60.*
- *Bhatt, S. (2004, June 12). The politics of education: A survey of Indian curriculum reforms. The Times of India.*
- *Chandra, B. (2009). India's struggle for independence. Penguin Books India.*
- *Chaudhary, R., & Sharma, S. (2013). The political influence of education policies: A critical review of India's curriculum reforms. International Journal of Educational Development, 34(4), 564–576.*
- *Education Commission, Government of India. (2016). The influence of politics on curriculum reform in India. Retrieved from www.educationindia.gov.in*
- *Gupta, A., & Singh, M. (2015). Secularism or nationalism? The curriculum debate in India. Journal of Political Education, 28(2), 124–140.*
- *Jain, V. (2012). Political interference in education in India. Shree Publishers.*
- *Kumar, K. (1989). Social character of learning. Sage Publications.*
- *Kumar, K. (1991). Political agenda of education: A study of colonialist and nationalist ideas. Sage Publications.*
- *Kumar, K. (1992). What is worth teaching? Orient BlackSwan.*
- *Kumar, K. (2001). Prejudice and pride: School histories of the freedom struggle in India and Pakistan.*
- *Kumar, K. (2014). Political economy of education in India. Sage Publications.*
- *Kumar, K. (Ed.). (2016). Education and politics in India: Studies in organization, society, and policy. Orient BlackSwan.*
- *Ministry of Human Resource Development, Government of India. (2009). Education for all: The political role in curriculum design. Ministry of HRD.*
- *Ministry of Human Resource Development, Government of India. (2009). Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. Retrieved from http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/RTE_Act2009.pdf*
- *Mukherjee, M. (2005). History textbooks in India: Political and communal influences.*
- *Nair, P. (2005). Education and political influence in India: A historical perspective. National Book Trust.*
- *National Council of Educational Research and Training (NCERT). (Various years). Textbook controversies in India.*
- *National Council of Educational Research and Training (NCERT). (2005). National curriculum framework 2005: For school education. NCERT.*

- *Patwardhan, B. (2015). Impact of reservation policy on higher education in India: A critical appraisal. Economic & Political Weekly, 50(38), 100–108.*
- *Sharma, R. (2011). Education and nationalism in India.*
- *Sharma, S. (2007, March 5). Rewriting history: Political influences on textbooks in India. The Hindu.*